



फटकार : केवल कोटा में ही छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं : सुप्रीम कोर्ट

अक्षर संवाद

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों की बढ़ रही आत्महत्याओं को लेकर राजस्थान सरकार और पुलिस से जवाब तलब किया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पूछा कि ‘केवल कोटा में ही छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?’, और राज्य सरकार इस गंभीर मसले को लेकर अब तक क्या कदम उठा पाई है?

सर्वोच्च न्यायालय ने नीट की एक छात्रा की आत्महत्या के मामले में कोटा पुलिस द्वारा केवल इनक्वेस्ट रिपोर्ट दर्ज

साल 2025 में अब तक कोटा में 14 छात्रों ने आत्महत्या की है



करने और एफआईआर नहीं करने को अदालत के आदेशों की अवहेलना करार दिया। अदालत ने सवाल किया कि कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। यह हमारे पहले के आदेश की अवमानना है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को भी तलब किया और सख्त सवाल पूछे। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

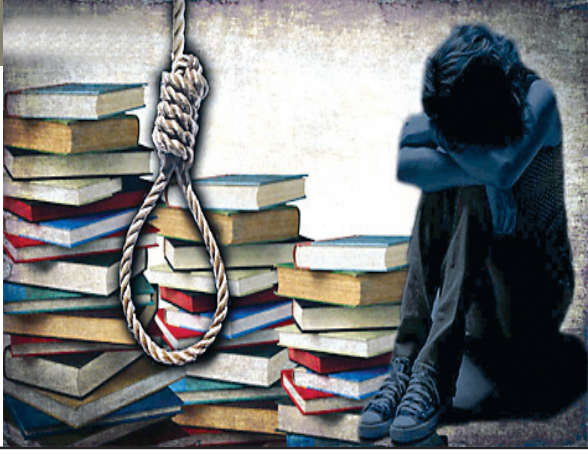
जस्टिस पारदीवाला ने राजस्थान सरकार के वकील से पूछा

■ आप एक राज्य के रूप में क्या कर रहे हैं?

■ ये बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और

केवल कोटा शहर में ही क्यों?

■ क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया?



संसदीय समिति की रिपोर्ट

आठ साल बाद भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना अधूरी

अक्षर संवाद

संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल मामलों की स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की है कि देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘इंस्टीट्यूट आफ एमिनेंस’ (IOA) योजना के तहत जिन बीस संस्थानों को अधिसूचित किया जाना है, उनमें से अब तक बारह संस्थानों को ही अधिसूचित किया गया है, लिहाजा यथाशीघ्र बाकी बचे आठ संस्थानों को भी अधिसूचित किया जाए।

इस रिपोर्ट को मार्च 2025 में संसद के पटल पर भी रखा गया था। रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि योजना शुरू होने के आठ साल बाद भी अधिसूचित होने वाले बीस संस्थानों में से आठ संस्थानों का अभी तक अधिसूचित नहीं होना दायित्व बोध का अभाव दर्शाता है। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की है कि शेष बचे विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए।

इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है?

शैक्षणिक संस्थान किसी भी राष्ट्र के निर्माण की बुनियाद होते हैं, इसलिए उनके पास बेहतरीन शिक्षण प्रणाली और छात्र सहायता के लिए सर्वोत्तम सुविधा होनी चाहिए, लेकिन 2017 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल नहीं था, इसलिए सरकार ने भारत में संस्थानों के लिए एक मान्यता योजना प्रस्तावित की। इस योजना को ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस’ (IOA) कहा गया, जिसके तहत भारत सरकार ने देश में बीस विश्वस्तरीय संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2017 में इस पहल की शुरुआत की।

अभी तक बारह संस्थानों को अधिसूचित किया गया है

इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (IOA) कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा अब तक बारह संस्थानों को ही उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। इनमें आठ सार्वजनिक संस्थान तथा चार निजी संस्थान हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जवाहरलाल नेहरू (जेएनयू) जैसे शिक्षण संस्थान को अभी तक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय की सूची में अधिसूचित नहीं किया गया है। एक संसदीय पैनल ने सरकार की उत्कृष्ट संस्थान योजना का विस्तार जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक करने की सिफारिश की है।

थोक में तबादला

राज्य सरकार ने 20 जिलों के डीसी बदले

पहली बार 16 आईएएस बने उपायुक्त

नाम	उपायुक्त
कर्ण सत्याथी	पूर्वी सिंहभूम
चंदन कुमार	पश्चिमी सिंहभूम
नीतिश सिंह	सरायकेला-खरसावां

अक्षर संवाद ■ रांची

छब्बीस मई को झारखंड सरकार ने बीस जिलों के उपायुक्त बदल दिए। इनमें सोलह अधिकारी पहली बार उपायुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे। कोल्हान की बात करें तो नीतिश सिंह को सरायकेला-खरसावां, चंदन कुमार को पश्चिमी सिंहभूम और कर्ण सत्याथी को पूर्वी सिंहभूम का उपायुक्त बनाया गया है। तबादले की इस कवायद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 जिलों में से 17 जिलों के डीसी की पोस्टिंग नहीं कर उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान देने को कहा गया है।

■ झारखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर (थोक में) तबादला किया गया है

■ 20 में से 17 जिलों के डीसी की पोस्टिंग नहीं की गई, उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान करने को कहा गया है

ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर लगाई रोक

हार्वर्ड विवि ने इस फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा टोका



अक्षर संवाद

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन नए-नए सिर्फे छोड़ते रहते हैं। इसी कड़ी में उनके नेतृत्व वाले प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को दाखिला देने की पात्रता को रद्द कर दिया है। नतीजतन, इस कार्यवाही को लेकर विश्वविद्यालय में पंजीकृत 800 भारतीय विद्यार्थियों सहित हजारों विद्यार्थियों की कानूनी स्थिति को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई है।

दूसरी तरफ इस फैसले के खिलाफ हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा टोक दिया है। हार्वर्ड

विश्वविद्यालय ने इसे असंवैधानिक प्रतिशोध बताया और कहा है कि सरकार की कार्यवाही प्रथम संशोधन का उल्लंघन करती है और इसका 7000 से अधिक वीजा धारकों पर तत्काल और विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। मुकदमे में हार्वर्ड ने कहा है कि सरकार ने एक कलम चलाकर वर्ल्ड के उस एक चौथाई विद्यार्थी समूह को मिटाने की कोशिश की है जो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हैं और जो विश्वविद्यालय और इसके मिशन में अहम योगदान देते हैं। मालूम हो कि हार्वर्ड कैंब्रिज मैसाचुसेट्स में अपने परिसर में लगभग 6800 विदेशी विद्यार्थियों को दाखिला देता है जो 100 से अधिक देशों से आते हैं।

प्रतिभा पलायन

विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन का आकर्षण बरकरार

अक्षर संवाद

महंगी फीस और खर्चीली व्यवस्थाओं के बावजूद उच्च अध्ययन के लिए लाखों शिक्षार्थी हर साल विदेश चले जाते हैं। ये शिक्षार्थी केवल कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया ही नहीं जाते, बल्कि उन देशों में भी जाते हैं, जहां की शिक्षा का स्तर भारत से कमतर है। हालात इतने चिंताजनक हैं कि इनमें से अधिकांश शिक्षा पूरी होने के बाद भी भारत वापस नहीं लौटते। ऐसे में प्रतिभा पलायन के साथ-साथ देश को विदेशी मुद्रा की भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब सवाल है कि देश में हजारों विश्वविद्यालय और पचास हजार के करीब महाविद्यालय होने के बावजूद शिक्षार्थी उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों का रुख क्यों कर रहे हैं।

आधारभूत संरचना का अभाव

प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अध्ययन- कक्षों, क्रीडा- स्थलों, शिक्षक कक्षों और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी, विदेश जाने वाले शिक्षार्थियों के पलायन का मुख्य कारण हो सकता है, साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेधावी शिक्षकों की कमी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधक बनी हुई है।



कैसे रुकेगा प्रतिभा पलायन

सर्वप्रथम विदेश जाने वाले शिक्षार्थियों को देश के ही विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना होगा। कर्मठ, लगनशील, मेधावी और शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। सरकारों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थानों की मूलभूत समस्याओं का गंभीरता पूर्वक निवारण और आधारभूत संरचना का समय के साथ पुनरुत्थान होते रहना चाहिए। विद्या के संस्थानों में आनंद एवं सुख का वातावरण हो इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे देश से बाहर जाकर अध्ययन करने वाले शिक्षार्थियों का पलायन रुके और विदेशी शिक्षार्थियों का भारत के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने की लालसा बढ़े।

देरी और हेराफेरी : ‘जल जीवन मिशन’ के प्रगति में देरी और अनियमितताओं से पीएमओ नाराज : दिए जांच के आदेश

अक्षर संवाद

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘जल जीवन मिशन’ का लक्ष्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। इस योजना को लागू करने के भले ही बड़े-बड़े दावे किए गए हों लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। योजना के प्रचार- प्रसार पर भारी रकम खर्च करने और आंकड़ों की हेराफेरी की जानकारी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं।



झारखंड में नल-जल योजना कछुए की गति से चल रही है

झारखंड में यह मिशन पूरी तरह फेल हो चुका है। राज्य में मार्च 2025 तक, 62,54,097 घरों में नल से पानी पहुंचाना था, लेकिन 34,40,792 घरों तक ही यह योजना पहुंची। यानी 55.02 प्रतिशत काम अभी तक हो पाया है। विडंबना यह है कि इनमें से भी कई ऐसे घर हैं जहां नल तो घरों तक पहुंच गए हैं लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी तमाम शिकायतें मिलेंगी जहां घरों में नल तो लगा दिए गए हैं लेकिन उनमें भ्रष्टाचार का टॉटी इतना टाइट है कि आज तक पानी नहीं निकला। अब इसे बदनसीबी कहें या सड़ रही व्यवस्था की बदबू, या कुछ और, लेकिन यहां की ग्रामीण जनता को प्यास बुझाने के लिए घर से दो-दो किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने का सिलसिला जारी है।

जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

‘जल जीवन मिशन’ में भारी अनियमितता और प्रगति में लेटलतपी की सूचनाओं ने पीएमओ की धड़कन बढ़ा दिया है। आठ मई को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्तीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक सौ पैंतीस जिलों में एक सौ तिरासी योजनाओं के निरीक्षण के लिए नित्यानवे नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया गया। इन अधिकारियों को तेईस मई को प्रशिक्षण भी दिया गया। इसमें निरीक्षण के मानकों की जानकारी भी दी गई। पीएमओ की ओर से यह सख्ती उस समय आई जब दो महीने पहले वित्त सचिव के नेतृत्व वाले पैनल ने मिशन के लिए प्रस्तावित 2.79 लाख करोड़ रुपए के बजट में छियालीस प्रतिशत की कटौती का सुझाव दिया था। वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों में कार्य अनुबंधों की लागत बढ़ाए जाने पर सवाल उठाए।

किस राज्य में कितना प्रतिशत काम हुआ

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
झारखंड	55.02	उत्तर प्रदेश	89.67
हरियाणा	100	तमिलनाडु	86.14
तेलंगाना	100	त्रिपुरा	88.95
पुडुचेरी	100	कर्नाटक	84.88
गुजरात	100	जम्मू कश्मीर	81.39
पंजाब	100	छत्तीसगढ़	81.05
हिमाचल	100	मणिपुर	79.59
अरुणाचल	100	ओड़ीसा	76.74
मिजोरम	100	आंध्र प्रदेश	73.88
उत्तराखंड	97.61	मध्य प्रदेश	67.78
लद्दाख	96.82	राजस्थान	56.54
नागालैंड	95.11	पश्चिम बंगाल	55.73
सिक्किम	91.60	बिहार	99.71
लक्षद्वीप	91.41	केरल	54.58
महाराष्ट्र	89.79		



रिपोर्ट: झारखंड में 20 वर्षों से बिना उपाध्यक्ष के ही चल रही विधानसभा

अक्षर संवाद

राज्य कानून की वार्षिक समीक्षा 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ‘संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत राज्य विधानसभाओं को यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनना होगा’ बावजूद इसके झारखंड विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव 20 वर्षों से नहीं हुआ है, और पद रिक्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि झारखंड सहित देश के कई राज्यों की विधानसभाओं में 5 महीने से लेकर 20 वर्षों से अधिक समय से इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है।



उपाध्यक्ष का प्रमुख कार्य

विधानसभा अध्यक्ष के त्यागपत्र या निधन के कारण पद रिक्त होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करना तथा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त करना और प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की अध्यक्षता करना।

अक्षर संवाद

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रिमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर अपनी महिला मित्र अनुष्का यादव के साथ फोटो शेयर कर बताया कि वह 12 साल से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। फोटो शेयर करने के कुछ क्षणों बाद पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही पोस्ट डाली।

समय बीतता रहा। रात करीब 10:42 बजे तेजू ने सफाई पेश की, बोले- मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया था, लेकिन यह सफाई कोई सुनने वाला नहीं था। मसला लालू परिवार का था तो सोशल मीडिया के इस दौर में बात पूरे देश में रफेल फाइटर जेट से भी तेज गति से फैल गई। ऐसी भद्द पिटेगी, लालू परिवार ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। एक



तरफ पार्टी और पब्लिक में कौतूहल था तो दूसरी तरफ लालू परिवार डेमेज कंट्रोल के उधेड़बुन में मशगूल था। फिर दूसरे दिन यानी रविवार को दोपहर 3:00 बजे लालू सोशल मीडिया पर

अवतरित हुए और उन्होंने भारी मन से बेटे को पार्टी और घर से निकाल देने का इजहार किया। राजनीतिक समझ रखने वाले पतेबाज इससे त्वरित डैमेज कंट्रोल की कोशिश मान रहे हैं, लेकिन एक सवाल सदैव मौजू रहेगा कि, जब वे सालों से रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने शादी क्यों की।

विडंबना यह है कि इन्हीं 12 वर्षों के दौरान तेजू विधायक और मंत्री तक बन गए। आशिक मिजाज तेजू ने जो कारनामा किया है अगर कोई आम आदमी करता तो अभी तक वह सलाखों के पीछे होता, लेकिन वे सियासी रसूख वाले परिवार के सदस्य हैं, और भारत में सियासी रसूख रखने वाले परिवारों के बच्चों को अय्याशी और खतरनाक कारनामों को अंजाम देने के लिए आजादी के पहले से ही काफी स्पेस छोड़ी गई है।

भारी मन से लालू ने घर और पार्टी से निकाला से नहीं

पिछले साल देश में 54 लाख लोग विस्थापित हुए



अक्षर संवाद

जिनेवा स्थित इंटरनल डिप्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर (आइडीएमसी) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल देश में बाढ़, तूफान व हिंसक घटनाओं के कारण 54 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा, इन्में दो तिहाई आंतरिक विस्थापन हुआ जो

मुख्यतः बाढ़ के कारण था। यह 12 वर्षों का सबसे अधिक आंकड़ा है। हिसा से जुड़े विस्थापन के 1700 मामले हैं जिनमें मणिपुर में 1000 लोग विस्थापित हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, भू- क्षरण और बांधों व तटबंधों के रखरखाव में कमी विस्थापन के अहम कारण हैं।

फुटपाथ सुनिश्चित करने को दिशा-निर्देश

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत फुटपाथ का इस्तेमाल करने का है अधिकार गारंटीशुदा है : सुप्रीम कोर्ट

अक्षर संवाद • जमशेदपुर

पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पैदल यात्रियों के लिए उचित फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया, और इसे उनका संवैधानिक अधिकार बताया। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां व जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि फुटपाथ के अभाव में पैदल यात्रियों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिससे उनके साथ दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। पैदल यात्रियों के लिए उचित फुटपाथ का होना आवश्यक है। यह ऐसे होने चाहिए कि जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो और इन पर से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य होना चाहिए।



साकची में फुटपाथ पर टेंपो वालों का कब्जा

साकची गोलचक्कर के बगल में सोनारी, कदमा, मानगो और बारीडीह जाने के लिए टेंपो स्टैंड बनाए गए हैं, लेकिन टेंपो चालकों के द्वारा स्टैंड में सवारियों को न बैठाकर फुटपाथ पर ही टेंपो को खड़ा कर सवारियों को बैठाया जाता है। पूरे फुटपाथ पर दिनभर टेंपो वालों को कब्जा रहता है। ऐसे हालात में लोगों को फुटपाथ की बजाए सड़क पर ही पैदल चलना पड़ता है जो की काफी जोखिम भरा होता है। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि गोलचक्कर पर ही दिनभर ट्रैफिक पुलिस के लोग गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं लेकिन उन्हें टेंपो वालों का यह आतंक और अतिक्रमण दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार लोगों को यह सब मालूम नहीं है, सबकुछ मालूम है, लेकिन अदृश्य और असहज करने वाले कारनामों ने उनकी आंखों को अंधा और कानों को बहरा बना दिया है।

संविधान का मखौल उड़ा रहे जिम्मेदार लोग

पैदल यात्रियों को फुटपाथ का इस्तेमाल करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीशुदा है, लेकिन जमशेदपुर शहर में इस अनुच्छेद

की धजियां उड़ाई जा रही हैं। पूरे शहर में फुटपाथ का अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमणकारियों में कानून का नाममात्र भी डर नहीं है, क्योंकि कानून का

पालन करवाने वाले जिम्मेदार लोग अंधे और बहरे बने हुए हैं। यह ख्वस्त हो चुकी व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है।

जमशेदपुर के सभी फुटपाथ अतिक्रमणकारियों के हवाले

संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत फुटपाथ लोगों को पैदल चलने के लिए बनाया जाता है लेकिन जमशेदपुर में एक भी फुटपाथ लोगों को पैदल चलने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि सड़कों के किनारे फुटपाथ नहीं बना है, बना तो है! लेकिन अतिक्रमण के कारण दिखाई नहीं देता, अर्थात वसूली और अतिक्रमणकारियों के बीच फुटपाथ का लोप हो गया है। सभी फुटपाथ पर दिनभर दुकानें सजी रहती हैं। अगर हम बात साकची क्षेत्र की करें तो साकची थाना से आई हॉस्पिटल वाया मुख्य गोलचक्कर होते हुए बंगाल क्लब तक, साकची मुख्य गोलचक्कर से भालुबासा तक, सड़क के दोनों ओर का फुटपाथ अवैध दुकानदारों के कब्जे में रहता है। फुटपाथ पर हर समय घड़ी दुकान,



चश्मा दुकान, मोबाइल कवर दुकान, गन्ना का ठेला, रेडीमेड कपड़ों की दुकान तथा सब्जी की दुकानें लगी रहती हैं। दूसरी तरफ बिष्टुपुर बाजार का भी यही हाल है, वहां भी फुटपाथ पर गाड़ियों की पार्किंग कराई जाती है। लोगों को मजबूरन सड़कों पर पैदल चलना पड़ता है जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।

अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी किसकी?

सड़क किनारे फुटपाथ पर होने वाला अतिक्रमण कई प्रकार से होता है। इसमें फुटपाथ पर लगे ठेले, छोटी-छोटी दुकानें और गाड़ी पार्किंग प्रमुख है। अगर फुटपाथ या सड़क का अतिक्रमण होता है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है! जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, ट्रैफिक पुलिस या स्थानीय थाने की? इन सवालों का जवाब कौन देगा!



ग्रामीण शासन प्रणाली की जानकारी

छात्रों ने किया बालिझोर ग्राम पंचायत का भ्रमण

अक्षर संवाद • चाईबासा

पिछले दिनों पश्चिमी सिंहभूम स्थित नोवामुंडी कॉलेज के छात्र- छात्राओं को पंचायती राज व्यवस्था की व्यावहारिक जानकारी के लिए बालिझोर ग्राम पंचायत का एक दिवसीय भ्रमण कराया गया। भ्रमण प्रस्थान से पूर्व प्राचार्य डॉ. मनोजीत विश्वास ने कहा कि छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी जरूरी है। यह भ्रमण छात्र- छात्राओं को ग्रामीण शासन प्रणाली को नजदीक से जानने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह भ्रमण छात्रों के लिए भविष्य निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। प्राचार्य मनोजीत विश्वास ने जानकारी प्रदान की कि भविष्य में भी अन्य पंचायतों का भ्रमण कराने की योजना बनाई गई है। पंचायत कार्यालय पहुंचने पर, वहाँ उपस्थित मुखिया रवि सामड़, उप मुखिया सचिवा लकड़ा, डुका साई के मुंडा श्री घसुवा बारजो सहित अन्य वार्ड सदस्यों ने कॉलेज के शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं का स्वागत किया। ग्रामीण मुंडा श्री घसुवा बारजो ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह पहली बार है जब किसी शैक्षणिक संस्था ने इस क्षेत्र में पंचायत सचिवालय का औपचारिक शैक्षणिक



भ्रमण किया है। इससे न केवल विद्यार्थियों को पंचायत की कार्यप्रणाली समझने में सहायता मिलेगी, बल्कि पंचायत प्रतिनिधियों को भी अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग होने की प्रेरणा मिलेगी। छात्रों द्वारा किए गए सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देते हुए मुखिया श्री रवि सामड़ ने छात्रों को बताया कि ग्राम पंचायत के माध्यम से पानी, बिजली, सड़क, नाली निर्माण, शौचालय योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल भवन निर्माण, वृद्धा एवं विधवा पेंशन योजना, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यों का संचालन किया

जाता है। उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि किस प्रकार गाँव में जलापूर्ति के लिए जलमीनार, सोलर मोटर पंप, तथा हैंडपंप की व्यवस्था की गई है।

बिजली की आपूर्ति के संदर्भ में उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अधिकांश घरों में बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। सड़कों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कच्ची और पक्की सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के विषय में बताया गया कि

गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों को पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण आदि की सुविधाएं पंचायत की निगरानी में नियमित रूप से दी जा रही हैं। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचायत की सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने हाट बाजार कर व्यवस्था, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों का उपयोग आदि की भी जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को बताया कि पंचायत सामाजिक समस्याओं जैसे डायन प्रथा, गुटखा- पान की लत आदि के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाती है। साथ ही गांव में होने वाले छोटे- मोटे झगड़ों का निपटारा भी पंचायती स्तर पर किया जाता है, जिससे न्याय त्वरित और सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रत्येक पंचायत में ज्ञान केंद्र (पुस्तकालय) की स्थापना की गई है, जहाँ कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। पंचायत के सदस्यों के साथ बैठक के बाद छात्रों ने अनुभव किया कि पंचायती राज व्यवस्था केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि यह ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक सहभागिता की आत्मा है। दूसरी तरफ नोवामुंडी कॉलेज द्वारा की गई इस सार्थक पहल पर कॉलेज के शिक्षकों के साथ उपस्थित छात्र काफी उत्साहित नजर आए।

राज्यपाल ने किया चानकु महतो की प्रतिमा का अनावरण



अनावरण : झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 15 मई को पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत चाकुलिया प्रखण्ड के भालुकुबिधा ग्राम में स्वतंत्रता सेनानी चानकु महतो की प्रतिमा का अनावरण किया।

जेल अदालत में पांच वादो का निष्पादन

घाघीडीह केंद्रीय कारा व घाटशिला उपकारा में जेल अदालत का आयोजन

अक्षर संवाद • जमशेदपुर

हालिया दिनों घाघीडीह केंद्रीय कारा व घाटशिला उपकारा में जेल अदालत तथा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा मौजूद रहीं ,वहीं न्यायिक दंडाधिकारी, रेलवे कोर्ट चाईबासा वचुअल रूप से जुड़े थे। शिविर में विशेष कर वैसे बंदियों को चिन्हित किया गया , जिनके परिवार वाले जमानत के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। साथ ही वैसे बंदी, जो अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं है, उनके बारे में जानकारी ली गई। न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा ने कारा के

बंदियों से एक-एक कर बात की तथा उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। जेल में रहन-सहन, भोजन, न्यायिक सहयोग तथा परिवार के संबंध में, हर मुद्दे पर बंदियों से बात की गई। जेल अदालत में कुल-05 वादो को रखा गया, जिसमें 05 वादो का निष्पादन हुआ, जिसमें 05 बंदी लाभांश्चित हुए। 05 बंदियों में से 01 बंदी तत्काल कारा से मुक्त हुआ। 01 बंदी पर अन्य वाद लंबित रहने तथा शेष 03 बंदी अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने के फलस्वरूप कारा से मुक्त नहीं किये जा सके। कारा में चिकित्सा शिविर (Medical Camp) लगाया गया, जिसमें कारा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य जाँच किया गया।

जांच अभियान : स्कूलों के नजदीक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर कार्रवाई



अक्षर संवाद • जमशेदपुर

पिछले दिनों अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, शताब्दी मजुमदार के द्वारा कदमा में डीबीएमएस स्कूल के आसपास तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के विरुद्ध जांच

अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई सीओटीपीए अधिनियम, 2003 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के अंतर्गत की गई, जो शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।

बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को झारखंड से निकाला जाएगा

अक्षर संवाद • देश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत से निकालने की कवायद शुरू हो गई है, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र भेजा है। झारखंड सरकार को भी इससे संबंधित पत्र भेजा गया है। राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी राज्य सरकारें भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें होलिडिंग सेंटर में रखें ताकि उन्हें उनके देश डिपोर्ट किया जा सके। पत्र में यह भी कहा गया है कि होलिडिंग सेंटर में पहले घुसपैठियों की जांच होगी फिर उन्हें बीएसएफ और कोस्ट गार्ड को सौंपा जाएगा।

पंजाब से अवैध शराब मंगाकर बिहार भेज रहे तस्कर

वाहन जांच के दौरान 600 पेटी अवैध शराब बरामद

अक्षर संवाद • पलामू

पिछले दिनों राज्य कर सहायक आयुक्त/राज्य कर पदाधिकारी, पलामू अंचल, डाल्टनगंज के द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स से लदा हुआ एक ट्रक जब्त किया गया था, जिसकी वाहन संख्या RJ 04GA-5448 है। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रक को टी.ओ.पी.-02 परिसर में रखा गया था। 14 मई को राज्य कर पदाधिकारी की एक टीम द्वारा वाहन की जाँच की गई, जिसके पश्चात् वाहन चालक मौके से फरार हो गया और उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर 16मई की रात में राज्य कर पदाधिकारी, पलामू अंचल की टीम के द्वारा टी.ओ.पी.-02 प्रभारी को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कर दिया गया है, अतः वाहन को चालक सुरीन्दर सिंह को सुपुर्द कर मुक्त किया जाए। अब ऐसे में पुलिस को संदेह हुआ तो मामले की गहराई से जाँच प्रारंभ की गई। वाहन की विधिवत जाँच के दौरान पुलिस ने कपड़ों के



बोरे के बीच छुपाकर रखी गई 600 पेटी विदेशी शराब (Royal Stag, McDowells No-01 Original) बरामद की, जिन पर "For Sale in Punjab Only" अंकित था। पृष्ठतछ के क्रम में लुधियाना, पंजाब के रहने वाले गिरफ्तार चालक सुरीन्दर सिंह, ने बताया कि यह शराब वाहन मालिक तगा राम के द्वारा पंजाब से भेजी गई है। महेन्द्र यादव उर्फ धोनी (तिलैया) तथा पप्पू साव (बरही) के द्वारा इसे बरही व कोडरमा में उतारकर स्पिरिट मिलाकर, दोहरी बोतल बनाई जाती तथा झारखंड लेबल लगाकर बिहार में बेचने



की योजना थी।इस अवैध तस्करी के संबंध में शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें तगा राम (वाहन मालिक), पिता- पूनमा राम, पता- झीपोनियो की ढाणी, कुम्पलिया, बाड़मेर,राजस्थान, मोहन (पहेला चालक – फरार), सुरीन्दर सिंह (गिरफ्तार चालक) के नाम दर्ज हैं। जब्त सामग्री में Royal Stag (750ml) – 420 पेटी × 12 बोतल = 5040 बोतल, Mc Dowells No-01 (750ml),180 पेटी × 12 बोतल = 2160 बोतल, तथा रेडीमेड कपड़ों के साथ 120 सफेद प्लास्टिक के बोरो की बरामदगी की गई है।

बेरोजगारी और पलायन : युवा बेरोजगार संघ का शक्ति प्रदर्शन

अक्षर संवाद • चाईबासा

बढ़ती बेरोजगारी और पलायन को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम स्थित गुआ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने एकजुट होकर गुआ काली मंदिर के समीप झारखंड सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। युवाओं में झारखंड सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश था। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा

कि पिछले कई सालों से गुआ में युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। यहाँ के युवा पलायन को मजबूर हैं। दूसरी तरफ गुआ में ठेका श्रमिक (नोटशीट) में काम करने के लिए भी 4-5 लाख रुपये की मोटी रकम देनी पड़ रही है। ये गुआ के युवाओं का दुर्भाग्य है। प्रदर्शन में उपस्थित सभी युवाओं ने एक स्वर में कहा है कि अब गुआ के किसी भी युवा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना इस प्रदर्शन को हम उग्र आन्दोलन में बदल देंगे।

प्रदर्शनकारी युवाओं ने दलालों को भी चेतावनी दी कि अब गुआ में युवा बेरोजगार संघ का उदय हो चुका है, अब यहाँ दलालों की खैर नहीं। प्रदर्शन में युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष- उदय सिंह, उपाध्यक्ष - कैलाश दास, कोषाध्यक्ष - धनंजय पांडे, सचिव - बोरू सोनार सहित चूचू सिंह, तपोस दास, सुदीप दास, संजीत टैट्टी, बिनय मेहता, रवी मुखी, सागर दास, कानूराम लोहार आदि शामिल हुए।

सड़क निर्माण का सूचना बोर्ड बदलता रहा पर सूरत नहीं बदली

अक्षर संवाद • चाईबासा

मनोहरपुर और माइन्स, चिरिया से सरकार को प्रति माह करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है, पर चिरिया-अंकुआ की 5 किमी सड़क आज तक नहीं बन पाई है। वर्षों से यह सड़क जर्जर पड़ी है, हालांकि पिछले 10 सालों में इस सड़क का दो बार निर्माण कार्य शुरू हुआ, पर काम पूरा नहीं हुआ। पिछली बार वर्ष 2012 में सारंडा एक्सन प्लान में कार्य के दौरान उक्त सड़क का निर्माण कार्य भी स्वीकृत हुआ।

यह सड़क एनपीसीसी द्वारा बनाई जानी थी, लिहाजा 18 जुलाई 2012 को 357.18 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण का बोर्ड अंकुआ चौक के पास सड़क किनारे लगा दिया गया, पर काम शुरू नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना से एनपीसीसी द्वारा सड़क का निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी सिर्फ सूचना बोर्ड लगाने के सिवाय कोई कार्य नहीं हुआ। तीन गांव के हजारों लोगों के साथ- साथ चिरिया माइन्स से जुड़े



अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी व चिरिया आने जाने वाले लोग जर्जर कच्ची सड़क का उपयोग करने को विवश हैं। इस पर न तो सेल प्रबंधन, न राज्य सरकार, और न ही कोई जनप्रतिनिधि गंभीरता पूर्वक ध्यान दे रहे हैं। जर्जर सड़क के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। बरसात के दिनों में तो इस सड़क पर चलना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जर्जर

सड़क से प्रभावित लोगों का कहना है कि चिरिया माईंस के लोहा पत्थर से कई बड़े शहर चकाचौंध हैं, पर चिरिया व इस क्षेत्र के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सेल प्रबंधन को भी सिर्फ चिरिया माईंस से किसी तरह लोहा पत्थर निकाल ले जाने से मतलब रह गया है। क्षेत्र का विकास व क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को पूरी तरह सेल अनदेखा कर रही है।



अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में क्षेत्र की जनता लौह अयस्क खदान का उत्पादन ठप कर लौह अयस्क का डिस्पोज भी बंद कर देने को विवश हो

जाएगी, तब जाकर सेल प्रबंधन और सरकार सड़क निर्माण की दिशा में सार्थक पहल करेंगे। **बामिया माझी**, झामुमो नेता सह पूर्व जिला पार्षद, परिधनी सिंहगूम।



वर्तमान में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक ही परिवार के पास है। लां जोबा माझी सांसद हैं तो बेटा जगत माझी विधायक हैं, फिर भी दो दशकों से जर्जर सड़क

पर चलना क्षेत्र की जनता की मजबूरी हो गई है। जल, जंगल, जमीन का नारा लगावने वाली झामुमो की सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। **राजू सांडिल**, मुखिया, गांगदा पंचायत

बालिका आवासीय विद्यालय में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन निर्भीक होकर बुराइयों का प्रतिकार करें छात्राएं: धर्मेंद्र

अक्षर संवाद • जमशेदपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से हालिया दिनों जमशेदपुर स्थित सुंदरनगर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।इस मौके पर प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार एवं सुंदरनगर थाना के सब इंस्पेक्टर मिथुन स्वर्णकार मौजूद थे। इस दौरान विद्यालय में गठित लीगल लिटरेसी क्लब की छात्राओं के अलावे अन्य कक्षा की छात्राएं भी मौजूद थीं।

उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने सर्वप्रथम जिला विधिक सेवा प्राधिकार की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों से उन्हें अवगत कराया। तत्पश्चात उन्होंने भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकारों पर क्रमबद्ध तरीके से प्रकाश डाला। डालसा सचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई जरूरी प्रावधान किए गए हैं। वहीं नाबालिक बच्चियों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए पोक्सो जैसे कड़े कानून बनाए गए हैं।

उन्होंने बच्चियों से निर्भीक होकर समाज में होने वाली बुराइयों का प्रतिकार करने तथा इसकी शिकायत उचित फोरम में करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिला



डालसा सचिव को छात्राओं ने भेंट की पेंटिंग्स
कार्यक्रम समाप्त के बाद विद्यालय की छात्राओं की ओर से बनाई गई आकर्षक पेंटिंग डालसा सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार को भेंट की गई। इस दौरान

विधिक सेवा प्राधिकार कानून का अनुपालन एवं कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। जिले के सभी प्रखंड, पंचायत एवं सभी थानों में पारा लीगल वॉलंटियर्स प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जो आम लोगों की समस्याओं के समाधान में सहयोग करते हैं। मौके पर उपस्थित सुंदरनगर थाना के सब इंस्पेक्टर मिथुन स्वर्णकार ने कहा कि पुलिस नागरिकों की सुरक्षा एवं सहायता में हमेशा तत्पर रहती है। किसी भी तरह कानून का उल्लंघन होने की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने बच्चियों को भरोसा दिलाया कि वे असामाजिक गतिविधियों की

जानकारी पुलिस को दें। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के टोल फ्री नंबर 112 की जानकारी दी। साथ ही बच्चियों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, नालसा की ओर से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 15100 समेत अन्य विभागों के हेल्पलाइन नंबर से अवगत कराया गया। कार्यक्रम समापन के बाद विद्यालय की वार्डन सह प्राचार्य रीना सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में डालसा के प्रधान सहायक संजय कुमार, पीएलवी अरुण रजक, सुनील पोडे, जयंतो नंदी, सूरज कुमार, चैतन्य नायक, बालेश्वर दास, शिव रजक समेत अन्य मौजूद रहे।

नीति आयोग की बैठक में 31 राज्यों के प्रमुखों से प्रधानमंत्री ने कहा- टीम इंडिया की तरह काम करें तभी लक्ष्य संभव

अक्षर संवाद

नीति आयोग की दसवीं गर्वांग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत विकसित राज्यों से ही संभव है। चर्चा का मुख्य विषय भी था "विकसित राज्य के लिए विकसित भारत 2047"। मालूम हो कि नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति



आयोग की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सम्मिलित हुए। उन्होंने झारखंड का

प्रतिनिधित्व करते हुए खनन कंपनियों पर बकाया राशि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खनन कंपनियों

पर झारखंड का 1.40 लाख करोड़ रुपए बकाया है, इसका भुगतान यथाशीघ्र होना चाहिए।

राज्य में अनाधिकृत खनन के लिए कंपनियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए

नीति आयोग की बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में खनिज और कोयले के साथ-साथ अन्य खनिजों की बहुतायत है, जिनके खनन में प्रदूषण और विस्थापन एक बहुत बड़ा कारक रहा है। खनन कंपनियों द्वारा ली गई भूमि जो कि (नॉन पेमेंट आफ लैंड कंपनशेशन) में आती है, उनका एक लाख चार सौ पैंतीस करोड़ रुपए बकाया है, जिसको यथाशीघ्र मुहैया

कराया जाए और सी बी ए एक्ट में संशोधन कर खनन परचात कंपनियों को भूमि राज्य सरकार को पुनः वापस देने का प्रावधान किया जाए। राज्य में अनाधिकृत खनन के लिए कंपनियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। राज्य में कोल बेस्ड मीथेन गैस की बहुतायत है, जिसका तकनीकी रूप से इस्तेमाल कर ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में खनन कंपनियों को

कैप्टिव प्लांट लगाने की अनिवार्यता होनी चाहिए और कुल उत्पादन का 30प्रतिशत राज्य में इस्तेमाल होने से रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी। प्रदेश का वन क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों के समकक्ष है, जिससे आधारभूत संरचना के लिए क्लीयरेंस में देरी अवरोध बनती है, जिसका निवारण किया जाए और पूर्वोत्तर राज्यों को मिलने वाली विशेष सहायता झारखंड को भी प्रदान कराई जाए।

सीएम ने राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ कई अहम सुझाव दिए

नीति आयोग की बैठक में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विचारों को रखने के साथ कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना विकसित राज्य से होती है, जिसमें विकसित गांव को जोड़ना सबसे जरूरी है। विकसित भारत की मूल परिकल्पना का केंद्र

जनजातीय समुदाय के खानपान, पहनावा, संगीत, लोककला, वाद्ययंत्र तथा नृत्य को सहेजने की पहल छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण

अक्षर संवाद/रायपुर

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के पहले आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस संग्रहालय को आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और उनके जीवन शैली को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह संग्रहालय करीब 10 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया है।

संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पहचान हमारी सुंदर जनजातीय संस्कृति से है।



छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृत में विविधता है और हर जनजातीय समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। राज्य में 43 जनजातीय समुदाय हैं, और उनकी कई उपजातियां हैं। इसके साथ ही राज्य में विशेष पिछड़ी जातियां भी हैं। जनजातीय समुदाय का सुंदर संसार, इनका

खानपान, पहनावा, संगीत, लोक कला, वाद्य- यंत्र, नृत्य इन सब की झलक संग्रहालय में दिखेगी। इसमें 14 दीर्घा हैं, और हर दीर्घा एक विशेष थीम पर बनाई गई है। यह संग्रहालय युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

अंततः मारा गया जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा

अक्षर संवाद • लातेहार

लातेहार जिले के सलैया जंगल के पास पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा, साथी प्रभात के साथ मारा गया। पप्पू पर 10 लाख और प्रभात पर 5 लाख का इनाम घोषित था।

कौन था पप्पू लोहरा ?

नक्सली संगठन जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) का मुख्य कमांडर पप्पू लोहरा बहुत कम उम्र में ही माओवादियों के कमांडर संजय यादव के साथ संगठन से जुड़ गया था। बाद में नक्सली संगठन में आपसी विवाद होने के बाद उसने संजय यादव के नेतृत्व में ही जेजेएमपी संगठन बनाया, कुछ दिनों के बाद लेवी के पैसे

के बंटवारे को लेकर संजय यादव से भी विवाद हो गया और उसने संजय यादव की भी हत्या कर दी। संजय की हत्या करने के बाद पप्पू लोहरा स्वयं जेजेएमपी का सुप्रीमो बन गया। कुछ समय बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि पप्पू लोहरा का संगठन माओवादियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा खड़ा किया हुआ संगठन है।

भंडारण की कमी से बर्बाद हो रही उपज

पलामू के किसानों की उपज ही नहीं, उम्मीदें भी सड़ रहीं

अक्षर संवाद • पलामू

पलामू जिले के कई हिस्सों में किसानों को इस बार दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तो प्याज और आलू की अच्छी पैदावार हुई है दूसरी ओर इनके भंडारण और बाजार की उचित व्यवस्था न होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।लेस्लीगंज, पांकी, मनातू

ही नहीं बल्कि पूरे पलामू जिले में सरकारी कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और न ही बाजार व्यवस्था जहां किसानों के उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी हो। बहुतायत किसानों के पास भंडारण की निजी व्यवस्था नहीं है, लिहाजा उन्हें मजबूरी में खुले में उपज रखनी पड़ रही है, नतीजतन, प्याज और आलू सड़ने लगे हैं।



सरकार की चुप्पी किसानों के लिए चिंता का कारण

हालांकि सरकार ने पूर्व में कृषि उपज के लिए सुविधाएं बढ़ाने की बात कही थी, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। अब किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन इस संकट का स्थायी समाधान निकाले।

बाजार व्यवस्था ठप, समर्थन मूल्य की अनदेखी

स्थानीय मंडियों में खरीदारों की कमी और बिचौलियों की मनमानी ने किसानों की मुसीबत और बढ़ा दी है। उचित बाजार मूल्य न मिलने से कई किसान अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं।

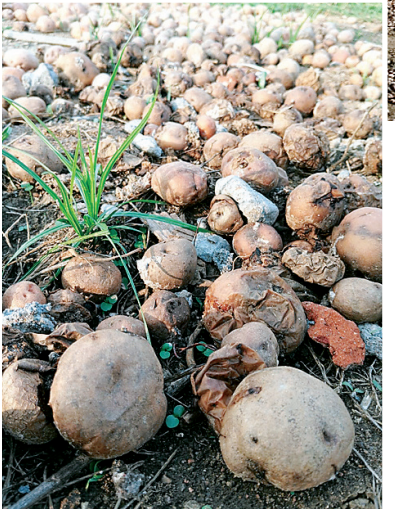
जिले के कई हिस्सों में किसानों को इस बार दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। आलू और प्याज की अच्छी पैदावार होने के बावजूद भंडारण और बाजार की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है



ग्रामीण बाजारों में उपज औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं

सरकारी कुव्यवस्था की मार झेल रहे किसान बाजार व्यवस्था और उचित भंडारण के अभाव में अपने उत्पाद ग्रामीण इलाकों में लगने वाले बाजार में बेचने के लिए मजबूर होते हैं,जहां बेचने और खरीदने वाले भी ग्रामीण क्षेत्र के किसान

और मजदूर तबके के लोग होते हैं। दूसरी तरफ बाजार के बिचौलिए भी किसानों की मजबूरी का भरपूर लाभ उठाते हैं।उचित बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपनी उपज बिचौलियों के पास बेचने को मजबूर होते हैं।



त्रुटिपूर्ण बीमा योजना

केंद्र सरकार किसानों के हित में फसल बीमा योजना चलाती है।यह योजना भी दो भागों में बंटी है।एबी और खरीफ फसल बीमा योजना।एबी फसल बीमा भी दो हिस्सों में बांटी गई है, एक मौसम आधारित फसल

बीमा योजना।इस योजना का लाभ सिर्फ कुछ ही राज्यों को मिल पाता है जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश शामिल है।

एबी फसल बीमा योजना में भी झारखंड राज्य को शामिल नहीं किया गया है। इस तरह झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है।

‘ट्रेवल एजेंटों’ द्वारा आपातकालीन कोटे के अनुरोध पर विचार नहीं होगा

सभी जोन के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए

अक्षर संवाद

आपातकालीन कोटे से सीट/बर्थ आवंटित करने के दुरुपयोग के बारे में प्राप्त शिकायतों के बाद रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह आपातकालीन कोटे के तहत रेलगाड़ियों में सीट/ बर्थ आरक्षण के लिए ट्रेवल एजेंट से प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार न करें। रेल मंत्रालय ने अपने लिखित निर्देश में कहा है कि आपातकालीन कोटे से अनाधिकृत रूप से सीट आवंटित करने के प्रयास के मामले मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए हैं, लिहाजा सभी जोन के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए।



रेल मंत्रालय ने आरक्षण कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और दलालों के बीच सांटगांट को रोकने के लिए अधिकारियों को दिया सुझाव

करने के लिए एक रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें सभी ऐसे अनुरोधों को डायरी में दर्ज किया जाएगा, जिसमें यात्रा

का पूरा विवरण और यह भी दर्शाया जाएगा कि अनुरोध किस स्रोत से प्राप्त हुआ है। अधिकारियों को सचेत करते हुए मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि ट्रेवल एजेंट से प्राप्त आपातकालीन कोटे से सीट/ बर्थ आवंटित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने अधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे समय-समय पर आरक्षण केंद्रों का निरीक्षण करें, ताकि आरक्षण कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और दलालों के बीच सांटगांट को रोक जा सके।